IJASRM

International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Vol. 2 Issue 3, Mar 2017.

www.ijasrm.com

ISSN 2455-6378

ग्रामीण एवं कृषि विकास (आर्थिक सुधार एक अभिनव पहल)

निशा विश्वकर्मा
शोधार्थी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल

भूमिकाः–

भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है । 1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई है । जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गयी है भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरकर आया है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो न केवल इसलिए भी भारत की आधी से भी अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप मे जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है । 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए है । एवं विभिन्न नीतिगत उपायों के द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप एक बड़ी सीमा तक खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई है ।

मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है । यहां तीन चौथाई जनसंख्या कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसाय के जरियें जीवनयापन करती है । जनसंख्या में वृद्धि के साथ–साथ प्रदेश की खाद्यान जरूरते भी बढ़ी है । परन्तु उत्पादन कम हो रहा है । पिछले चालिस वर्षो में खाद्यान उत्पादन मध्यपदेश में कुल उत्पादन में लगातार घटता जा रहा है । अर्थव्यवस्था के वैश्विकरण के कारण जहा एक तरफ विकास की नई संभावनाये उपलब्ध हुई है वही नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इस शोध–पत्र में मध्यप्रदेश के कृषि क्षेत्र में आर्थिक सुधार की नीति अपनाने के बाद हुए कृषि उत्पादन पर प्रभाव को जानना अतिआवश्यक है ।

भारत आज के विकसित देशों से पुराना देश है वर्ष 1951 से क्रियान्वित विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश विकास की राह पर अग्रसर है । किन्तु फिर भी अनेक आर्थिक संकटों का भारतीय अर्थव्यवस्था को सामना करना पड़ा है । इस आर्थिक संकटों का सामना करने के लिए सरकार ने आर्थिक सुधारों का अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सभी क्षेत्रों पर प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है । प्रस्तुत शोध पत्र में कृषि विकास को जानने की कोशिश की गई है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

(1) पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को जानना
(2) फसलो की उत्पादकता को ज्ञात करना
(3) कृषि विकास को जानना
(4) कृषि उत्पादन तकनीक का अध्ययन करना

शब्द कुंजी :–

कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादन, अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुधार, योजनाएं तकनीक, उत्पादकता

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थानः–

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है । पिछले दो दशकों से अधिक अवधि में औद्योगीकरण के संगठित प्रयास के बावजूद कृषि का गौरवपूर्ण स्थान बना हुआ है । देश का सबसे बड़ा उद्योग होने के कारण कृषि देश की 65 प्रतिशत जनता की जीविका का स्त्रोत है । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत इसके कार्यभाग को जान सकते है ।

(1) राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा

(2) कृषि और रोजगार का ढांचा

IJASRM
International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Vol. 2 Issue 3, Mar 2017.
www.ijasrm.com
ISSN 2455-6378

(3) उद्योग एवं कृषि

(4) अन्तरर्राष्ट्रीय व्यापार एवं कृषि

(5) आर्थिक आयोजन एवं कृषि

सामान्य आर्थिक विकास के लिए कृषि विकास अनिवार्य :–

भारत में कृषि के महत्व का एक कारण यह भी है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए कृषि का विकास एक अनिवार्य शर्त है ।

प्रो. रेगनर नर्क्स का कहना है कि कृषि पर आधारित अतिरिक्त जनसंख्या को वहां से हटाकर नए आरम्भ किए गए उद्योगों मे लगाया जाना चाहिए । नर्क्स का मत यह है कि इससे एक ओर कृषि उत्पादिता में वृद्धि होगी, और दूसरी ओर अतिरिक्त श्रम शक्ति का उपयोग करके नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा सकेगी ।

आर्थिक सुधार एवं म.प्र. में कृषि उत्पादकता एवं सभावनाएं म0प्र0 में आर्थिक सुधार की नीतियों के प्रत्यक्ष लाभ कृषि की उत्पादकता पर दिखाई देते है । म0प्र0 की प्रमुख फसलों में गेहूँ, चावल, सोयाबीन, कपास, गन्ना, जवार, मक्का आदि की उत्पादकता आधिक है । अतः इसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए म0प्र0 की कृषि की संभावनाएं अधिक है। समस्या है वित्त की समस्या , विपणन की समस्या, बीज, सिचाई तकनीक आदि की यदि हम म0प्र0 का विकास चाहते है तो हमे सर्वप्रथम कृषि का विकास करना होगा, क्योकि यह का समाज अधिकांश कृषि पर आधारित अपना जीवन यापन कर रहा है । विश्वव्यापी (मंदी) के समय भी म0प्र0 की कृषि पर कोई विशेष विपरीत प्रभाव नही पड़ा । आर्थिक संकट का प्रभाव तो उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों पर अधिक पड़ा है । जैसा कि राहुल मुखर्जी ने कहा है । कृषि क्षेत्र मे संकट एवं विपरित का राजनैतिक परिणाम अर्थ सहायता हो सकता है इस अर्थसहायता से लाभ हानि किसानों को मिलता है । न कि गरीब किसानों को । ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी की समस्या का निदान करने लिये बड़े पैमाने पर अतिरिक्त संसाधन जुटाने होगें ।

यदि राज्य सरकार द्वारा योजनाएं बनाकर वित्तीय सहायता प्रदान कर कमियों को दूर किया जा सकता है । म0प्र0 का देश की राष्ट्रीय आय में कृषि उत्पादकता द्वारा विशिष्ट स्थान हो सकता है । म0प्र0 की कृषि ग्रामीण विकास, सामाजिक विकास रोजगार में अहम भूमिका अदा करती है ।

ग्रामीण विकास आर्थिक सुधारों के आधार पर भारत के लिए गांव आर्थिक समृद्धि के प्रतीक है देश तभी फलेगा फूलेगा जब उसकी आत्मा के रूप में गांव की प्रगति हो गावों का सर्वागीण विकास हो यहा सब पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है । आज ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण समाज को जीवन पद्धति मे सुधार हेतु आर्थिक सुधार एवं कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता है । यह काम ग्राम पंचायत द्वारा आसानी से किया जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास शासन द्वारा प्रदान की सेवाओं, वर्तमान में बदलते परिवेश, वैधानिक अविष्कार अनुसंधान और तकनीक द्वारा ही संभव हो पाया है ।

आर्थिक सुधार का कृषि पर प्रभावः–

आर्थिक सुधार के बाद से ही भारतीय ग्रामों को सामाजिक आर्थिक परिवेश में बदलाव देखने को मिल रहा है । ग्रामीण लोगों में आमतौर पर सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है । उसका प्रमुख कारण नीतिगत कृषि एवं ग्रामीण विकास में सुधार होना है जिसमें आधारभूत ढांचों एवं कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना प्रमुख है । कृषि उत्पादन को निर्धारित करने वाले प्राकृतिक स्त्रोत–मिट्टी जलवन, जलवायु वर्षा और भू–आकृति तथा कृषि में अपनाई जाने वाली तकनीक सामाजिक आर्थिक संरचना, शोध अध्ययन नीति प्रमुख है ।

IJASRM
International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Vol. 2 Issue 3, Mar 2017.
www.ijasrm.com
ISSN 2455-6378

कृषि में संसाधन की अपनी सीमाएं है । अधोसंरचना तकनीकी, आदि सतत् कृषि विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है संसाधनों का संयोजन तब हो जब हम कृषि विकास के साथ ग्रामीण विकास कर सकेगे लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ।

कृषि फसलों का उत्पादन (टन में)

क्र.	फसले	1990–91	200–01	2010–11	2011–12	2012–13
1	खाद्यान्न	176.39	196.81	244.49	259.29	255.56
2	दाले	14.26	11.08	18.24	17.09	18.45
3	तिलहन	18.61	18.44	32.48	29.80	31.01
4	कपास	9.84	9.52	33.00	35.20	34.00
5	जूट	9.23	10.56	10.62	11.40	11.30
6	गन्ना	241.05	295.96	342.38	361.04	338.96

गहन कृषि :– जब किसी खेत में वर्ष में एक से अधिक फसले उगाई जाती है उसे फसलो की गहनता कहते है फसलो की गहनता को सूचकांक द्वारा मापा जाता है यदि किसी खेत में वर्षभर में केवल एक ही फसल होती है तो उसका सूचकांक 100 होता है यदि वर्ष दो फसल उगाई जाती है तों उस स्थिती में फसल सूचकांक 200 होता है। शस्य गहनता सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र

शस्य गहनता

वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल

सूचकांका———————————————— ग100

कुल कृषि भूमि

फसलो की गहनता को प्रभावित करने वाले घटक

1. पर्याप्त वर्षा 2. उर्वरको का प्रयोग, 3. यंत्रीकरण 4. फसलो का हेर फेर

तकनीकि कृषि में नवीन प्रवृत्तियों का प्रभाव

1. उत्पादकता में वृद्वि 2. उत्पादन लागत मे कमी 3. समय की बचत 4. मशीन का उपयोग 5. श्रम की कुशलता में वृद्वि 6. उपभोक्ता को लाभ 7. हरित क्रांति 8. प्रकृति पर निर्भरता मे कमी

राज्य जैविक कृषि नीति 2011 :–

मध्यप्रदेश सरकार नें जैविक कृषि नीति 2011 कों 2 जुलाई 2011 को मंजूरी दी है। इस नीति के प्रमुख उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की विभीषिका एवं वैश्वीकरण का कृषि उत्पादों पर पड़नें वाले प्रभावों को कम करना तथा उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में वृद्वि लाना है। इस नीति कों समस्त धान्य फसलों, सब्जियों, फल, मसाले एवं सुगन्धित एवं औषधीय फसलों पर लागू किया जाएगा। जैविक कृषि नीति 2011 के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है।

- वन आधारित उत्पादों को प्रोत्साहन देना।

IJASRM
International Journal of Advanced Scientific Research and Management, Vol. 2 Issue 3, Mar 2017.
www.ijasrm.com
ISSN 2455-6378

- स्वतः जैविक क्षेत्रों का संरक्षण तथा अधिसूचन करना।
- जैविक एवं नैसर्गिक रंगों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- जैविक कृषि हेतु नीति–निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अत्यधिक सिंचित एवं उर्वरक प्रयोग का समाधान करना।
- जैविक उत्पादों के विपणन हेतु विकास केन्द्र स्थापित करना।
- सुरक्षित एवं अक्षय कृषि को बढ़ावा देना।
- जैविक प्रमाणीकरण को प्रोत्साहन देना।
- सहभागी गारण्टी पद्वति को लागू करना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानक स्तरों के बीच सन्तुलन स्थापित करना।

निष्कर्ष एवं सुझावः–

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो खाद्यान्न पूर्ति के साथ–साथ रोजगार प्रदान करता है लोगो की जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन नही बल्कि एक व्यवसाय के रूप में उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है । यहा निर्यातक वस्तुओं का भी उत्पादन होता है । ग्रामीण विकास की आधार शिला भी कृषि ही है इसके विकास से म.प्र. के साथ समस्त राष्ट्र में फसल उत्पादन में आत्म निर्भरता के साथ–साथ निर्यातक राज्य भी बन सकेगा यदि सरकारे योजनाएं बनाकर एवं वित्तीय सहायता प्रदान करें तो उत्पादकता को विशिष्ट स्थान प्रदान किया जा सकता है । यह कहा जा सकता है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास में आर्थिक सुधारों का महत्वपूर्ण योगदान है । जिससे कृषि सामाजिक, आर्थिक एवं ग्रामीण विकास में महत्वूपर्ण भूमिका अदा करती है ।

सुझावः–

(1) कृषि विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का अयोजन ।

(2) उन्नत बीजो का उपयोग होना चाहिए ।

(3) तकनीकी का उपयोग

(4) बहुफसलीय कार्यक्रम

(5) ड्रीप सिस्टम का विज्ञापन

(6) योजनाओं का विस्तार

(7) सरल प्रक्रिया एवं कम ब्याज दर

(8) ग्रामीण विकास हेतु आधारित संरचना

(9) ग्रामीण विकास कार्यक्रम

संदर्भः–

(1) भारतीय अर्थव्यवस्था –46 वां संस्करण –2009 रूद्र–दत्त के.पी.सुन्दरम

(2) पत्रिका–

1. संचालक आर्थिक एवं साहित्यकीय कृषि
2. कृषि सांख्यकीय एवं कार्पोरेशन विभाग भारत सरकार

(3) स्वयं के साक्ष्य

(4) कृषि ूमइेपजम एवं प्दजमतदमज

(5) पत्र एवं पत्रिका

(6) मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जबर सिंह परमार
प

i